मध्यप्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

अंशुमन शुक्ला

(सिविल अपील सं. 3498/2008)

06 अगस्त, 2014

[टी. एस. ठाकुर, वी. गोपाला गौड़ा और सी. नागप्पन, जे.जे.]

मध्य प्रदेश मध्यम अधिकारन अधिनियम, 1983: धारा 19 — धारा 5 की प्रयोज्यता सीमा अधिनियम, 1963 का यू/एस दायर किया गया। 19 1983 का अधिनियम-आयोजितः धारा 19 में तीन महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है-इसके विपरीत, उच्च न्यायालय को किसी भी समय एक पुरस्कार की प्रतिलिपि के लिए बुलाने के लिए स्वतः संज्ञान शक्ति प्रदान की जाती है-इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायी इरादा की प्रयोज्यता को बाहर करना था 1983 के अधिनियम के धारा 19 तक सीमा अधिनियम-संशोधन दाखिल करने में देरी अक्षम्य है-गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गए मामले-सीमा अधिनियम, 1963 -धारा 5.

न्यायालय द्वारा अपीलों को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

मध्य प्रदेश मध्यम अधिकार अधिनियम, 1983 की खंड 19 की खंड 5 की प्रयोज्यता का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है और न ही यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत है कि विधायी इरादा पर सीमा अधिनियम की खंड 5 अधिनियम की खंड 19 के आवेदन को रोकना था। [पैरा 39] [375-एफ]

नगर पालिका परिषद, मुरैना बनाम अग्रवाल निर्माण कंपनी 2004 (एल. आई.) एम. पी. जे. आर. एस. एन. 55; नगर पालिका परिषद, मुरैना बनाम अग्रवाल निर्माण कंपनी 2004 एम. एल. जे. 374 -अस्वीकृत।

नसीरुद्दीन और अन्य बनाम सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577:2003 (1) एस. सी. आर. 634; भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470; 2001 (3) पूरक एस. सी. आर. 619-लागू नहीं होता है।

मुकरी गोपालन बनाम चेप्पिलट पुथनपुरविल अबूबकर (1995) 5 एस. सी. सी. 5:1995 (2) पूरक एस. सी. आर. 1; हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एस. सी. सी. 133:1974 (3) एस. सी. आर. 31-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2004 (ii) एमपीजेआर एसएन 55	अस्वीकृत	पैरा 2
2004 एम. एल. जे. 374	अस्वीकृत	पैरा 5
2003 (1) एस. सी. आर. 634	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 6
2001 (3) पूरक एस. सी. आर. 619	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 6
1995 (2) पूरक एस. सी. आर. 1	संदर्भित	पैरा 27
1974 (3) एस. सी. आर. 31	संदर्भित	पैरा 27

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी याचिका सं 3498/2008

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर पीठ के सिविल संशोधन सं. 1330/2003 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.06.2005 से।

के साथ

सी ए सं. 1145/2009

अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ अपीलार्थियों की ओर से।

अक्षत श्रीवास्तव, मंजीत कृपाल प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश वी. गोपाला गौड़ा, जे. द्वारा पारित किया गया था :-

1. सिविल अपील सं 3498/2008 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सी. आर. 1330/2003 आदि मामले में दिनांक 13.4.2005 के निर्णय और आदेश पर भरोसा करते हुए पारित किया गया। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा के सी. आर. सं.1330/2003 में पारित दिनांक 30.6.2005 के आदेश से का सिविल अपील सं. 3498/2008 उत्पन्न होता है।संबद्ध सिविल अपील सं.1145/2009 के सी. आर. सं. 1/2006 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 4.7.2006 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

2. सिविल अपील सं 3498/2008 की सुनवाई इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा की गई थी, जिसमें दिनांक 12.05.2008 के फैसले के माध्यम से यह राय दी गई थी कि नगर पालिका परिषद, मुरैना बनाम अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले का सही निर्णय नहीं लिया गया था और इस प्रकार, मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता थी। यह भी राय दी गई कि एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए मामले का रिकॉर्ड भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। इस तरह यह मामला हमारे सामने विचार के लिए आया है।

3. चूँकि दोनों अपीलें समान हैं, सुविधा के लिए, हम सी.ए. सं.3498/2008 के आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे जो यहाँ नीचे बताए गए हैं;

प्रत्यर्थी ने मध्य प्रदेश मध्यम अधिकार अधिनियम, 1983 (इसके बाद "1983 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 7 के तहत एक याचिका दायर की। पक्षों

के बीच निष्पादित कार्य अनुबंध के बारे में दावे।याचिका को मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 18.6.2003 के फैसले के माध्यम से आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।24.04.1998 से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 6,05,624-ब्याज 12% की राशि प्रदान की गई थी।

4, पीड़ित होने कारण, अपीलकर्ताओं ने सिविल संशोधन सं.1330/2003 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 1983 के अधिनियम की खंड 19 के तहत, सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 5 के तहत एक आवेदन के साथ (जिसे इसके बाद "सीमा अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए।

5. उच्च न्यायालय ने संशोधन में अपने दिनांक 1 के आदेश में कहा कि नगर पालिका परिषद, मुरैना बनाम अग्रवाल निर्माण कंपनी मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार?निम्नलिखित के प्रश्न पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हैः

> "क्या सीमा अधिनियम की खंड 5 का प्रावधान उच्च न्यायालय में खंड 19 के तहत दायर संशोधन पर लागू होता है?"

6. निर्देश दिए जाने के बाद, नगरपालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) में मामला इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।याचिका को सीमा पर खारिज करते समय, यह 27.08.20043 दिनांक एक आदेश में देखा गया था;

> "हमारे विचार में विवादित निर्णय में कोई कमजोरी नहीं है।नसीरुद्दीन और अन्य के मामले में प्राधिकरण।सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एस. सी. सी. 577 का सही तरीके से पालन किया गया है।भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470 के

मामले में भी इस न्यायालय द्वारा इसी विचार को गलत बताया गया है।विशेष अनुमति याचिका को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।"

7. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांकित 13.04.2008 के आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमा स्तर पर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना एक बाध्यकारी मिसाल है, और इसका पालन नीचे की अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए।हालाँकि यह भी देखा गया कि 1983 के अधिनियम की खंड 19 के तहत स्वप्रेरणा संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए जो संशोधित किए जाने वाले आदेश की प्रकृति और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पुनरीक्षण याचिका को कानून के अनुसार विचार के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

8. सिविल संशोधन सं. 1330/2003, जिसे 80 दिनों के समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण पीठ द्वारा अपने दिनांक 13.04.2005 के आदेश में दिए गए कारणों के लिए खारिज कर दिया गया था।

9. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने पुनरीक्षण को खारिज करने के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।इस अदालत की खण्ड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से यह राय व्यक्त की थी कि नगर पालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) के मामले को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और इसकी आवश्यकता है। एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया और आगे निर्देश दिया गया कि मामले के अभिलेखों को एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।इस प्रकार यह मामला विचार के लिए हमारे सामने आया।

10. सबसे पहले, प्रतिद्वंद्वी कानूनी प्रस्तुतियों की सराहना आदेश के लिए, 1983 के अधिनियम की खंड 19 पर विचार आदेशना आवश्यक होगा, जो संशोधन और इसकी सीमा से संबंधित है।जो नीचे लिखा है:-

> "19. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति-(1)-उच्च न्यायालय किसी भी समय या किसी व्यथित पक्ष द्वारा अधिनिर्णय के तीन महीने के भीतर उसे किए गए आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसमें इस अधिनियम के तहत अधिनिर्णय दिया गया है और ऐसी मांग की प्राप्ति पर न्यायाधिकरण संबंधित अधिनिर्णय और स्वप्रेरणा अभिलेख उस न्यायालय को भेजेगा या भेजेगा।
>
> (2) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण -
>
> (क) उसने ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या
>
> (ख) इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है; या
>
> (ग) कानूनी रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्य किया है; या
>
> (घ) स्वयं या कार्यवाहियों का गलत संचालन किया है; या
>
> (ई) एक ऐसा पुरस्कार दिया है जो अमान्य है या कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा अनुचित रूप से प्राप्त किया गया है,

उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझता है।

(3) उच्च न्यायालय इस खंड के तहत किसी भी संशोधन का निर्णय लेने में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की संख्या 5) की खंड 115 के तहत संशोधन का निर्णय लेने में करता है।

(4) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में अपने आदेश की एक प्रति को न्यायाधिकरण के लिए प्रमाणित कराएगा।

स्पष्टीकरण।-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक पुरस्कार में एक "अंतरिम" पुरस्कार शामिल होगा।"

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं।

12. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा। पुनरीक्षण याचिका को 1983 के अधिनियम की खंड 19 के तहत प्राथमिकता दी गई है और 80 दिनों की देरी को इसके द्वारा माफ कर दिया जाना चाहिए था।

13. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि 1883 के अधिनियम की खंड 19 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते समय सीमा अधिनियम की खंड 5 का प्रावधान लागू होगा। मामले की परिस्थितियों में अधिनियम के तहत स्वप्रेरणा संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से भी विफलता थी।

14. यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्ण पीठ के आदेश में निर्दिष्ट निर्णय मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।

15. 1983 के अधिनियम की खंड 19 के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि खंड 19 का परंतुक केवल वर्ष 2005 में जोड़ा गया था, हालांकि यह मुद्दा पूर्व-संशोधन प्रावधान से संबंधित है, जब ऐसा परंतुक, विशेष रूप से विलंब को माफ करने की शक्ति प्रदान करने वाला नहीं था।

16. यह भी तर्क दिया गया कि यह प्रश्न-कि क्या अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक "न्यायालय" है या नहीं, यह तय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1983 के अधिनियम की खंड 19 (3) में प्रावधान है कि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय उसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 115 के तहत पुनरीक्षण का निर्णय लेने में करता है।

17. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नगरपालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) के मामले में आदेश सही कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं करता है।आदेश को मौन रूप से पारित किया गया था और यह इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि यह न तो उपरोक्त कानूनी मुद्दों और प्रस्तुतियों पर विचार करता है और न ही इसे ध्यान में रखता है

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान और अधिनियम की योजना या मुद्दे पर विभिन्न मामले कानून।नगरपालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे यहां उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर लागू नहीं होते हैं और तथ्यों पर अलग-अलग होते हैं।

18. दूसरी ओर, संबद्ध सी ए सं संख्या 1145/2009 में प्रतिवादी द्वारा दायर

जवाबी शपथ पत्र में कहा गया है कि अपीलार्थी यह कहते हुए इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवेदन को सीमा अधिनियम की खंड 5 के तहत प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि, देरी की माफी के लिए आवेदन के एक खाली अवलोकन से, यह देखा जा सकता है कि आवेदन को अधिनियम की खंड 19 के संशोधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकता दी गई थी। अधिनियम की संशोधित खंड 19 का लाभ अपीलार्थियों को नहीं दिया जा सका क्योंकि प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बनाए गए थे। अधिनियम की खंड 19 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए समाप्ति अवधि के बहुत बाद, 29.08.2005 पर संशोधन लागू हुआ। उच्च न्यायालय ने बहुत सही निर्णय दिया है कि संशोधन समय की पाबंदी थी।चूंकि विलंब को माफ करने के लिए आवेदन दायर करने की तारीख पर ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था, इसलिए अपीलार्थी देरी को माफ करने के हकदार नहीं थे।

19. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पक्षकारों की ओर से आग्रह की गई उपरोक्त तथ्यात्मक और प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों के संदर्भ में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

(1) क्या सीमा अधिनियम के प्रावधान मध्य प्रदेश मध्यम अधिकारन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों पर लागू होते हैं?

(2) कौन सा आदेश?

बिन्दु संख्या 1 का उत्तर

20. मध्य प्रदेश मध्यम अधिकार अधिनियम, 1983 01.03.1985 से लागू हुआ। यह उन विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन पर राज्य सरकार या एक सार्वजनिक उपक्रम (पूरी तरह से या काफी हद तक राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या

नियंत्रित) एक पक्ष है और उससे प्रासंगिक या उससे जुड़े मामलों के लिए।

21. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन कार्य अनुबंध से संबंधित या ऐसे किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से उत्पन्न या संबंधित सभी विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए 1983 के अधिनियम की खंड 3 के संदर्भ में किया गया है।

22. अधिनियम की खंड 7 में विचारण के संदर्भ का प्रावधान किया गया है, चाहे समझौते में मध्यस्थता खंड हो या नहीं। अधिनियम की खंड 7-ए उस आधार पर विवरण प्रदान करती है जिसके आधार पर संदर्भ याचिका दायर की जानी है।

23. अधिनियम की खंड 19 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि पीड़ित पक्ष पुरस्कार की तारीख के तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। उच्च न्यायालय को देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करने के लिए 2005 में इस खंड में संशोधन किया गया था। चूँकि यह विवाद 2005 से पहले का है, इसलिए वर्तमान मामले में असंशोधित अधिनियम का प्रावधान लागू होगा।

24. सीमा अधिनियम, 1963 सीमा कानून पर सामान्य कानून है।

25. सीमा अधिनियम की खंड 5 में प्रावधान है कि सीमा अवधि समाप्त होने के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि देरी का पर्याप्त कारण था।

26. सीमा अधिनियम की खंड 29 बचत खंड है। उप-धारा (2) इस प्रकार हैः

> ''(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के मुकदमा अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है, वहां खंड 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे

जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के मुकदमा निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, खंड 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जहां तक और जिस हद तक वे ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।"

इस प्रकार, उप-खंड (2) में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम की खंड 4 से 24 किसी भी अधिनियम पर लागू होगी जो सीमा की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है, जब तक कि उन्हें उस विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं किया जाता है।

27. इस न्यायालय ने मुकरी गोपालन बनाम चेप्पिलट पुथनपुरविल अबूबकर के मामले में इस सवाल की जांच की कि क्या सीमा अधिनियम केराला भवन (पट्टा और किराया) नियंत्रण अधिनियम, 1965 पर लागू होगा।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि केरल अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अधिनियम सीमा की अवधि निर्धारित करता है, जो सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि से अलग है, और उपरोक्त (पट्टा और किराया) नियंत्रण अधिनियम में सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है, इस प्रकार, वे धाराएं केरल अधिनियम पर लागू होंगी।

सीमा अधिनियम की खंड 29 (2) के प्रावधानों की जांच करते समय यह देखा गयाः

"8.उपरोक्त प्रावधान पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर इसकी प्रयोज्यता और सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 तक के प्रावधानों के तंत्र के

आयात के लिए उक्त प्रावधान को लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित दो आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैः

(i) किसी भी मुकदमा, अपील या आवेदन के संबंध में किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का प्रावधान होना चाहिए।

(ii) इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का उक्त निर्देश सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा अनुसूची अवधि से अलग होना चाहिए।''

28. आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो निम्नलिखित निहितार्थ होंगेः

"9. यदि उपरोक्त दो अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो खंड 29 (2) द्वारा निर्धारित परिणाम स्वतः ही सामने आ जाएंगे।ये परिणाम इस प्रकार हैंः

(i) ऐसे मामले में सीमा अधिनियम की खंड 3 लागू होगी जैसे कि विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अनुसूची अवधि अनुसूची द्वारा अनुसूची अवधि थी।

(ii) किसी मुकदमा, अपील या आवेदन के लिए ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के लिए धारा 4 से 24 (आक्षेपात्मक) वाले सभी प्रावधान उस हद तक लागू होंगे, जिस हद तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।" [इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया]

29. इसके अलावा, हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा के मामले में, इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह जांच करते हुए कि क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों पर सीमा अधिनियम लागू होगा, निम्नानुसार कहाः

> "17. .....लेकिन हमें यह देखना है कि क्या विशेष कानून की योजना, जो कि इस मामले में अधिनियम है, और उसमें प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधानमंडल ने इसे अपने आप में एक पूर्ण संहिता बनाने का इरादा किया है जो अकेले उसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करे। यदि प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदान किए गए लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में सहायता के लिए नहीं लिया जा सकता है। हमारे विचार में, ऐसे मामले में भी जहां विशेष कानून एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी न्यायालय के लिए यह जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक उन प्रावधानों की प्रकृति या विशेष कानून की विषय-वस्तु और योजना की प्रकृति उनके संचालन को बाहर करती है।"

30. हुकुमदेव नारायण यादव (उपरोक्त) के अनुसार, भले ही विशेष कानून में कोई स्पष्ट बहिष्करण मौजूद न हो, अदालत विशेष कानून के प्रावधानों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क्या विधायी इरादा सीमा अधिनियम के संचालन को बाहर करना था।

31. 1983 के अधिनियम की खंड 19 में तीन महीने की सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा अवधि का सीमा अधिनियम की अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, खंड 19 सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 4 से 24 के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है।

32. अब हम अपना ध्यान नसीरुद्दीन अन्य अन्य (ऊपर) के मामले की ओर मोड़ते हैं, जिस पर इस अदालत ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए नगरपालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) के मामले में भरोसा रखा था। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या राजस्थान परिसर (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 की खंड 13 (4) के तहत किरायेदार द्वारा किराए की जमा राशि राजस्थान की खंड 5 सीमा अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक आवेदन है।

33. किरायेदार द्वारा जमा की प्रकृति की जांच करते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "46. .....15 दिनों के भीतर किरायेदार द्वारा जमा सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 5 के अर्थ के भीतर एक आवेदन नहीं है।चूंकि जमा के लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए खंड 5 के प्रावधानों को बढ़ाया नहीं जा सकता है जहां अधिनियम की खंड 13 की उप-खंड (4) के तहत किसी आदेश का पालन करने में चूक होती है।''

34. इसके अलावा, यह समझाते हुए कि सीमा अधिनियम की खंड 5 क्यों लागू नहीं होती है, न्यायालय ने कहाः

> "सीमा अधिनियम की खंड 5 के प्रावधानों का अर्थ उनकी खंड 3 को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए। सीमा अधिनियम या किसी

विशेष क़ानून के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन दायर करने के लिए वाद हेतुक उत्पन्न होना चाहिए। वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन वाद हेतुक कारण को जन्म नहीं देता है।न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने में विफलता पर अधिनियम के तहत तत्काल परिणाम प्रदान किए जाते हैं। न्यायालय चूक को केवल तभी माफ कर सकता है जब अधिनियम न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करता है और अन्यथा नहीं। मामले के उस दृष्टिकोण में हमारे पास यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि सीमा अधिनियम 1963 की खंड 5 का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।" [इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया]

उस मामले में निर्णय को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि सीमा अधिनियम की खंड 5 को राजस्थान अधिनियम, खंड 13 (4) पर लागू नहीं होने का कारण, विचाराधीन विशिष्ट प्रावधान की प्रकृति थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीमा अधिनियम की खंड 5 खंड 13 (4) पर लागू नहीं होती है, क्योंकि किरायेदार द्वारा किराए की जमा राशि को सीमा अधिनियम की खंड 5 के उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं कहा जा सकता है। इस मामले को वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीमा अधिनियम की खंड 5 को 1983 के अधिनियम की खंड 19 के उद्देश्य के लिए आवेदन मिला है, और जब न्यायाधिकरण ने पुरस्कार पारित किया तो अपीलकर्ता को वाद हेतु प्राप्त हुआ है।

35. अब हम अपना ध्यान दूसरे मामले यानी भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण (उपर्युक्त) की ओर आकर्षित करते हैं, जिस पर इस न्यायालय ने नगरपालिका परिषद, मुरैना (उपर्युक्त) के मामले में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए

भरोसा किया था।उसमें मुद्दा यह था कि क्या सीमा अधिनियम की खंड 4 से 24 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की खंड 34 पर लागू होगी।

36. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की खंड 34 (3) के शब्द इस प्रकार हैंः

> "34.(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस डेफ से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस पर वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या। यदि उस तारीख से खंड 33 के तहत कोई अनुरोध किया गया था, जिस तारीख को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया थाः
>
> बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिन की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है। लेकिन उसके बाद नहीं।"[इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया]

खंड 34 के प्रावधान की जांच करते हुए, लोकप्रिय निर्माण मामले (उपरोक्त) में न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "8. यदि खंड 34 के परंतुक में केवल एक ऐसी अवधि के लिए प्रावधान किया गया होता जिसके भीतर न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता था, तो यह सीमा अधिनियम की खंड 4 से 24 को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता क्योंकि 'खंड 5 की प्रयोज्यता को हटाने के लिए केवल सीमा की अवधि का प्रावधान पर्याप्त नहीं है"[इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया]

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि खंड 5 खंड 34 (3) पर लागू नहीं होती है, यह

अभिनिर्धारित किया गया कि "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्दों की उपस्थिति सीमा अधिनियम की खंड 5 के स्पष्ट अपवर्जन के रूप में कार्य करती है।

> "12. जहाँ तक 1996 के अधिनियम की खंड 34 की भाषा का संबंध है, महत्वपूर्ण शब्द 'हैं लेकिन उसके बाद उप-खंड (3) के परंतुक में उपयोग नहीं किए गए हैं।हमारी राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की खंड 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा, और इसलिए उस अधिनियम की खंड 5 के अनुप्रयोग पर रोक लगाएगा। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी।यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, वाक्यांश 'लेकिन उसके बाद नहीं' को पूरी तरह से अनुचित बना देगा।व्याख्या का कोई भी सिद्धांत इस तरह के परिणाम को उचित नहीं ठहराएगा।" (न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

37. 1983 के अधिनियम की खंड 19 में तीन महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है।इसके विपरीत, उच्च न्यायालय को किसी भी समय पुरस्कार का रिकॉर्ड मांगने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायी इरादा 1983 के अधिनियम की खंड 19 पर सीमा अधिनियम की खंड 5 की प्रयोज्यता को बाहर करना था।

38. हमारी राय में, इस सवाल पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण वर्तमान मामले में मुद्दे का जवाब देने के लिए एक अदालत है या नहीं, क्योंकि संशोधन दाखिल करने में देरी उच्च

न्यायालय के समक्ष हुई है, न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष।

बिन्दु संख्या 2 का उत्तर

39. ऊपर दर्ज कारणों के आलोक में, हमारी राय है कि नगर पालिका परिषद, मुरैना (ऊपर) के मामले का फैसला गलत तरीके से किया गया था। सीमा अधिनियम की खंड 5 1983 के अधिनियम की खंड 19 पर लागू होती है। इसमें कोई स्पष्ट बहिष्करण शामिल नहीं किया गया है, और न ही यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत है कि विधायी इरादा 1983 के अधिनियम की खंड 19 पर सीमा अधिनियम की खंड § के आवेदन को रोकना था।विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के लिए जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, अर्थात् नसीरुद्दीन (ऊपर) और लोकप्रिय निर्माण (ऊपर) को तथ्यों के साथ-साथ लागू कानून दोनों के संदर्भ में अलग किया जा सकता है, और इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

40. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम अपीलार्थियों के पक्ष में सकारात्मक रूप से हमारे द्वारा बनाए गए बिंदुओं का जवाब देते हैं। विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और दोनों अपील की अनुमति है। पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी की निंदा की जाती है और मामलों को गुण-दोष के आधार पर जांच करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें।

देविका गुजराल अपीलों को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।